>

Title: Discussion on points arising out of the answer given by the Minister of women and child Development on October, 17, 2008 to starred Question No. 07 regarding Malnutrition.

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर) : सभापति महोदया, मैंने बच्चों के कुपोषण के बारे में चर्चा की मांग की थी और सरकार ने उसे स्वीकार किया। आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

17 अक्तूबर, 2008 को तारांकित प्रश्न संख्या 7 का उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया था, जिससे हमारा समाधान नहीं हुआ था। यह स्वीकार किया गया था कि कुपोषित बच्चों की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है लेकिन उस समस्या का पूर्ण रूप से हल नहीं निकला है। यह समस्या सिर्फ महिला और समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा इसका मौनीटरिंग किया जाये, इसका पर्याय निकाला जाये या इस का हल निकले, इस विचार का मैं नहीं हूं। यह एक राष्ट्रीय समस्या है और एक मंत्रालय पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डालना उचित नहीं है। फिर भी इसके बावजूद मंत्रालय जो काम कर रहा है, उसमें कुछ दुरुस्ती होनी चाहिये। मैं इसे राष्ट्रीय समस्या के रूप में सरकार पर किसी प्रकार की टीका करने की बजाय, मैं चाहूंगा कि जिस क्षेत्र से हम लोग आते हैं, हर क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र होता है और ग्रामीणों में विशेषकर दुर्गम और आदिवासी क्षेत्रों में ऐसे कुपोषित बच्चों की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है। इसकी अनेक वजह हैं जिसे के लिये मैं विशेष तौर पर बताना चाहूंगा कि गर्भवती मातायें हैं, उनके गर्भ में जो बच्चा पलता है या जब पैदा होता है, वह कुपोषित होता है। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार ऐसे कुपोषित बच्चे पैदा होने से तीन साल से कम उम्र के 40 प्रतिशत बच्चों का वेट कम होता है।। इस वेट कम होने की वजह उनके शरीर में आयरन की कमी है। [s58] उन्हें एनीमिया हो जाता है, विटामिन की कमी होती है, ऐसे बच्चे कुपोषित होते हैं और ऐसे बच्चे फिर से पैदा न हों, अच्छे बच्चे पैदा हों, इसके लिए हमें माताओं की रक्तअल्पता का ख्याल करने की जरूरत है और इसके लिए मंत्रालय क्या प्रयास कर रहा है, यह मैं जानना चाहूँगा? आज हमारे देश में कुपोषित बच्चों की जो संख्या है, इसमें बीपीएल के अंतर्गत आने वाले जो गरीब परिवार हैं, 20 करोड़ 17 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसी संख्या दिखाई जाती है। मैं आपके माध्यम से यहाँ कहना चाहूँगा कि हम जो बीपीएल की लिस्ट बनाते हैं, उनमें जिन परिवारों को हम लेते हैं, इस पर भी कहीं न कहीं विचार होना चाहिए। गरीब लोगों के घर में जो बच्चे पलते हैं वे भी कुपोषण का शिकार होते हैं। बीपीएल में जो परिवार आते हैं, अगर 13 रूपया 66 पैसा से कम वह कमाता है तो वह बीपीएल में आता है और अगर वह 14 रूपया कमा लेता है तो वह बीपीएल की लिस्ट से निकल जाता है। यह राष्ट्रीय मानक बहुत गलत है, इस पर हमें विचार करना चाहिए कि इस मंहगाई के जमाने में अगर 14 रूपया कमाने वाला बीपीएल की लिस्ट से निकल जाता है तो इसका भी परिणाम ऐसे परिवारों के बच्चों पर होता है। कुल मिलाकर सरकार को सारे दृष्टिकोण से देखना चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रीशन, हैदराबाद की संस्था ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि ग्रामीण और शहरी दोनों तरह के बच्चे कुपोषण को प्राप्त हैं। इसकी यह वजह है कि उन्हें पोषक आहार नहीं मिलता है और पोषक आहार मिलने के जो अनेक कारण हैं उनमें गरीबी भी है। विटामिन-ए, विटामिन-बी, विटामिन-सी, आयोडीन और आयरन की जो कमी दिखाई देती है, इस वजह से ग्रामीण ही नहीं शहरी बच्चों में भी कुपोषण का जाल फैलता जा रहा है। मैं मंत्री महोदया से कहूँगा कि आपका मंत्रालय जो प्रमाणिक प्रयास कर रहा है वह कम हैं। इसमें हमारे अन्य मंत्रालयों जैसे, स्वास्थ्य मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है। ग्रामीण मंत्रालय की जिम्मेदारी इसमें इसलिए आती है कि जो बीपीएल की लिस्ट हम बनाते हैं उसमें ग्रामीण मंत्रालय को इसके बारे में सोचना चाहिए कि इसके कुछ मानक बदलें। हमारे महाराष्ट्र में कुपोषण के संदर्भ में एक सम्माननीय डॉ0 अभय भंग के नाम से एक समिति बनायी गई थी। उन्होंने महाराष्ट्र में एक रिपोर्ट बनायी है और उससे एक भयावह तस्वीर सामने आई है। उन्होंने उसमें लिखा था कि अगर हमने कुपोषण पर आज रोक नहीं लगाई तो वर्ष 2020 तक कुपोषण की समस्या अनियंत्रित हो सकती है। कुल मिलाकर कुपोषण की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है और यह दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसलिए मैं माननीया मंत्री महोदया से यह कहना चाहूँगा कि आप स्वास्थ्य मंत्रालय, आपूर्ति मंत्रालय, ग्रामीण मंत्रालय और साथ ही मानव रिर्सोसेज मंत्रालय, इन सभी मंत्रालयों की मदद लेकर इसका हल निकालने का प्रयास आपके मंत्रालय द्वारा होना चाहिए। कुपोषण को समाप्त करने की जिम्मेदारी हमें उठानी चाहिए। मैं चाहूँगा कि माताओं में रक्तअल्पता की जो कमी है, खून की कमी है उनके पोषण, अच्छे आहार के लिए आप क्या प्रयास करने जा रही हैं? गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले बच्चों को गरीबी के कारण जो पोषक आहार नहीं मिलता है उसके लिए भी आपको अच्छा प्रयास करना चाहिए और आप क्या करने जा रहीं है यह भी बताइए? मैं आपूर्ति मंत्रालय के माध्यम से, यहाँ पर मंत्री महोदय तो हैं नहीं, लेकिन मैं मंत्री महोदय से यह कहूँगा कि आपको इसमें खुद यह लिखना चाहिए कि जहाँ पर पीडीएस की दुकानें होती हैं, हर गॉव में दुकानें नहीं है और इसीलिए कई गॉवों में गरीब लोगों को सस्ता अनाज नहीं मिलता है। इस कारण से भी कई बार कई परिवारों के बच्चों में भुखमरी होती है। पीडीएस की शॉप हर गॉव में पहुँचे क्या इसके लिए आपके मंत्रालय द्वारा कोई प्रयास हो रहा है? अंत्योदय योजना के अंदर बीपीएल के लोगों को जो 35 किलो अनाज मिलता था उसको अब 20 किलो अनाज दिया जा रहा है, यह भी कुपोषण की एक वजह बनी हुई है। मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या इन सारी बातों के लिए आपने इन मंत्रालयों से मदद लेने का प्रयास किया है? जो मिड डे मील बच्चों को दिया जाता है उसमें क्वालिटी के साथ क्या कैलोरीज हैं, उसमें कैलोरीज के बारे में क्या आप मॉनीटरिंग करते हैं?

मैं मंत्री महोदया से आंगनवाडियों की संख्या के बारे में भी पूछना चाहूँगा, आंगनवाडियों की संख्या पर्याप्त नहीं है, अनेक गॉव ऐसे हैं जहाँ पर आंगनवाडियाँ नहीं है और आंगनवाडियाँ हैं भी तो वहाँ पर बिल्डिंग नहीं है, इमारत नहीं हैं। अनेक जगहों पर इमारत न होने की वजह से बच्चों को असुविधा है। [r59] कहीं कहीं आंगनवाड़ी है तो वहां बाथरूम भी नहीं है, कहीं इमारत नहीं है। इन बातों पर भी हमें ख्याल करना पड़ेगा कि हम जितने प्रयास करने जा रहे हैं, उनमें हमें सफलता नहीं मिल रही है। इन सारी बातों का अवलोकन होना चाहिए, मॉनीटरिंग होनी चाहिए और आने वाले दिनों में कुपोषण समाप्त करने के लिए क्या हम इससे हटकर कुछ और प्रयास करने जा रहे हैं? मैं पूछना चाहूँगा कि मैंने जितने मंत्रालयों के नाम गिनाए, क्या इन सारे मंत्रालयों की मदद लेने की आप पहल करेंगे? अगर करने जा रहे हैं तो उसके संबंध में अपने जवाब में बताएँ।

SHRI SURAVARAM SUDHAKAR REDDY (NALGONDA): Thank you, Madam. I would like to request the hon. Minister to take into consideration about the few issues that are arising in the Integrated Child Development Projects. I congratulate the hon. Minister and the Government for increasing the honorarium given to the Anganwadi helpers and workers which was overdue. For the last several years they were requesting for it and only last week the circular has come and now they are getting about Rs. 1,500. But still it is much less than the minimum wage prescribed by the Government of India.

Here the question is that such an important scheme which has to cover 80 per cent of the women who are anaemic and the children who are anaemic, this Integrated Child Development Project has to help these children to overcome these anaemic

problems and they should become healthy children, for that just opening of an ICDS Centre is not enough. As my hon. colleague has referred, in a number of places there are no buildings. A building without bathroom is of no use because the children need it, not only the helpers and workers. Drinking water facility is one of the most essential things.

More than 10,50,000 Anganwadis are working in this country and all of these people who are working in the Anganwadis, helpers and workers, who are about 20 lakhs, are being treated as volunteers. The Standing Committee on Labour has made a recommendation to the Government that they should also get regularisation of service; keep aside but at least they should get provident fund and ESI along with health insurance and life insurance schemes. I would like to request the hon. Minister whether these recommendations will be taken into consideration to make the ICDS programmes more successful and to give a minimum wage. Voluntary is really not voluntary, they are full-time workers. From morning to evening, up to 3.30 p.m., they are working. A volunteer's work is only for one or two hours.

In the States where the money is being given by the State Governments they are being given so many other works also to be done. Only in States like Goa, about Rs. 5,000 is paid to a helper; but in States like Bihar not a single pie is added by the State Government and only what the Central Government is giving, that is being paid to the Anganwadi workers. If the Anganwadi helpers and workers themselves become anaemic, they cannot serve the children.

MADAM CHAIRMAN : Please put a question to the hon. Minister.

SHRI SURAVARAM SUDHAKAR REDDY : Yes, Madam. So, I would like to request the hon. Minister to reply whether there is any possibility for improvement or increase in the honorarium being given, building bathrooms and providing drinking water facility along with the facilities that are being given to the unorganized labour, that are to be given to these helpers and workers.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY): Madam, first of all I would like to thank both the hon. Members Hansraj Gangaram Ahirji and Sudhakar Reddyji for having raised this very important issue. मैं बहुत खुश हूँ कि किसी ने सोचा कि इस बुनियादी मुद्दे को सदन में पेश करें ताकि सारे देश और दुनिया की नज़र इस पर जाए। यह वाकयी हमारे लिए शर्म की बात है कि देश में इतनी तरक्की होने के बाद भी आज हमारे यहां बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। [h60]कुपोषण की शुरूआत रातों-रात नहीं होती है। आपने सही कहा है कि एक माँ, जो खुद कुपोषण की शिकार है, उसकी कोख में पलते हुए बच्चों को भी कुपोषण की शिकायत हो जाती है। इसे देखते हुए देश के प्रधान मंत्री श्री मनमोहन सिंह ने और यूपीए चेयरपरसन के सुझाव से हमने एक खास मंत्रालय इन्हीं मुद्दों की देख-रेख करने के लिए बनाया है। पिछले तीन साल से यह मंत्रालय काम कर रहा है और you will be able to appreciate that we have actually doubled the money for supplementary nutrition. We have doubled it so that all beneficiaries are able to avail of it. We have increased the money for nutritious food and इसीलिए हमने कहा है कि इसमें बीपीएल का कोई फर्क नहीं है। जितने बच्चे आंगनबाड़ी में आते हैं, सभी को एक नजर से देखा जाता है और they are all beneficiaries and they are eligible. बीपीएल की सीमा हम पर लागू नहीं होती है। जो बच्चे आंगनबाड़ी में आते हैं, उन सभी को हम पौष्टिक आहार देने का प्रयास करते हैं।

We have also asked for convergence. Hon. Member Shri Sudhakar Reddy is absolutely right that we must have built up infrastructure. First, we should have safe drinking water because 90 per cent of water-borne diseases are what target our children. As a result of that, they have low resistance to infections and they have diarrhoea. Almost 11 per cent of our children die before the age of 5 because of diarrhoea disease. We have introduced oral re-hydration which is not enough, but it is a stop gap arrangement. Built up infrastructure is mandatory. So, we are doing convergence with other Ministries where we have requested Panchayati Raj to allocate the land for us where we can have *anganwadis* built. I have been requesting the other Ministries also to come hand in hand with us so that we can built up these *anganwadis*.

Now, the number of *anganwadis* has also been increased. Anyone can come forward and ask for an *anganwadi* on demand so that we can set up it. उसमें कोई पोपुलेशन नार्मस नहीं हैं। एक जमाने में हम लोग जरूर कहते थे कि जब तक इतने लोग नहीं आएंगे, तब तक हम आंगनबाड़ी नहीं खोलेंगे। जहां हमें जरूरत महसूस होती है, वहां हम आंगनबाड़ी जरूर चलाते हैं। आंगनबाड़ी टीचर्स और हैल्पर्स के लिए हमने ओनोरेरियम बढ़ा कर पहली अप्रैल, 2008 से बैकलॉग से एरियर देते हुए, सारे देश के आंगनबाड़ी वर्कर्स और हैल्पर्स को दे रहे हैं। मैं मानती हूं कि गांव के लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं because they are the most important people, they are the most important key to development.

हम गर्भवती महिला की बच्चे पैदा होने तक और छह महीने बाद तक इनकी देखभाल करते हैं। हम फ्री खाना देते हैं, पौष्टिक आहार देते हैं, चिकित्सा करते हैं, टीकाकरण करवाते हैं, प्री स्कूल एजुकेशन सिखाते हैं। इसलिए मैं हाउस की स्पोर्ट चाहती हूं कि यह औरत जो इतना काम कर रही है, कुछ सहूलियत तो दें, ताकि एक बिल्टअप आंगनबाड़ी हो so that they can actually cook and actually do some positive work and look after the children. कुपोषण को समझने के लिए हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि malnutrition impacts on the productivity of a nation. यह सिर्फ बच्चों का मामला नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ महिला या बच्चों की बात है, इसलिए हमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। बच्चे की देखभाल सिर्फ एक औरत ही करेगी, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इसका हमारे देश की तरक्की पर असर पड़ता है। सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा हम बच्चों को जो शिक्षा देते हैं, पौष्टिक आहार देते हैं, उससे इनके सिखने के तरीके पर भी असर पड़ता है। जैसे आज के दिन मध्य प्रदेश में बच्चों की कुपोषण के कारण मृत्यु हो रही है। We have lot of deaths

due to malnutrition. हाँ, यह अलग परम्परा है कि हम संसद में हमेशा कहते हैं कि there are no deaths by malnutrition. क्योंकि कुपोषण से कौन मरता है, इसका हमें कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। लेकिन यह सच है कि कुपोषण की वजह से शरीर कमजोर बन कर हम दूसरी बीमारियों का शिकार बनते हैं।[r61] और उससे हम मर जाते हैं। यह सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, बच्चे तो नाजुक होते हैं। वे लोग छोटी उम्र के हैं, उन पर जल्दी असर नज़र आता है, मगर बड़ों पर भी इसका बहुत असर पड़ता है।

मैडम, मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि अगर इस पार्लियामेंट के बाहर मैं आपका परीक्षण कराऊंगी तो आप में से 50 परसैंट से ज्यादा लोग इस हाउस में भी कुपोषण के शिकार होंगे।...(व्यवधान) अगर आप देखने में तन्दुरूस्त लग रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप तन्दुरूस्त हैं। ...(व्यवधान)

श्री सुकदेव पासवान (अररिया) : आप जांच करवाइए।

श्रीमती रेनुका चौधरी : मैं जांच करवा दूंगी। हम आपका भी देखभाल करते हैं।...(व्यवधान)

सभापति महोदया : एनेक्सी में यह प्रोविज़न है, आप जांच करवाइए।

श्रीमती रेनुका चौधरी : इसके बड़े मल्टी-फेसेटिड प्रोबलम्स होते हैं और इसमें लो-प्रोडक्टीविटी हो जाती है, जिसकी वजह से देश की कमाई कम हो जाएगी। फिर वे लो-इनकम और पावर्टी के शिकार हो जाते हैं। It is a very catch-22 situation. हमें अपनी ह्यूमन केपिटल को इरोड नहीं करना चाहिए। हमने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स (एमडीजी गोल्स) पर दस्तखत किया है। हमारा इरादा है, that we will improve maternal health, and target to reduce it to three-quarters between 1990 and 2015. मेटरनल मोरटेलिटी रेट हमें कम करनी चाहिए। इसकी कोशिश में हम इंस्टीटयूशनल डिलीवरीस और ये सब सिखाते रहते हैं। हमारे आंगनवाड़ी में जो औरत आती है, उसे हम समझाते रहते हैं। मगर एक बात है कि हम सारा पैसा केन्द्र सरकार से राज्य सरकारों तक पहुंचा देते हैं, पार्लियामेंट में हम जवाब देते हैं, मगर राज्य सरकारें अपनी जिम्मेदारी पहचानने में और उठाने में कई बार पीछे रह जाती हैं। It is very unfortunate....(व्यवधान)

सभापति महोदया: इसके लिए मोनिटरिंग कमेटी बनाइए।

श्रीमती रेनुका चौधरी : हमारी कई मोनिटरिंग स्कीम्स हैं। मगर जब तक वे जवाब नहीं देंगे, तब तक यह समस्या हल नहीं होगी। This problem cannot be resolved unless you hold the States accountable.

MADAM CHAIRMAN: You can get the Utilization Certificate and the number of beneficiaries in it.

श्रीमती रेनुका चौधरी : वह तो आप भी जानती हैं, उसे मुझे हाउस में कहना भी नहीं चाहिए। हमने cost sharing मैथड्स रखे हैं, between the Centre and the States with effect from the financial year 2009-2010. 90 परसैंट हम दे रहे हैं, दस परसैंट सप्लीमेंट्री न्यूट्रीशन के लिए हम नार्थ-ईस्ट से पूछ रहे हैं ताकि उनकी अपनी एक ऑनरशिप ऑफ द स्कीम होगी और वे जवाबदेह होंगे। In rest of the States, we have said 50-50 for supplementary nutrition and 90-10 for all other components of all States other than the North-East. इनके लिए हम कह रहे हैं और आज के दिन हमने जो एसएनपी बढ़ा दिए हैं, इसकी वजह से, we should be able to feed our children with nutritious food.

मैडम, मेरी एक राय है कि जो भी खाना खिलाते हैं, उसमें हमें फोर्टीफिकेशन जरूर करनी चाहिए, क्योंकि कई बार गांवों में फ्लोराइड पानी होता है और अगर सेफ ड्रिंकिंग वाटर बच्चों तक नहीं पहुंचता है तो फ्लोराइड शरीर से जो भी न्यूट्रीशन है, उसे खींच लेता है, उसकी वजह से हड्डियां एवं दांत नरम हो जाते हैं और बच्चों के टेढ़े पांव एवं टेढ़ा शरीर आपको नज़र आता है, आप जब अपने-अपने क्षेत्र में फ्लोराइड एरियाज़ में जाकर देखते हैं। ऐसी कई समस्याएं आती हैं। हमारे पास ग्यारह स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जिनमें हमारी हाई डेंसिटी मैल-न्यूट्रीशन चल रही है। इन स्टेट्स में अगर हम तुंत इसका कुछ इमीडिएट रिएक्शन नहीं करेंगे तो बहुत बुरा होगा। इसलिए हमने आज के दिन देश भर में, we have recognised the information. We are strengthening the Management Information System. We are revising the cost norms of training component of ICDS scheme. हम रिवार्ड्स इंसेंटिव्स और एवार्ड्स दे रहे हैं, जहां आईसीडीएस फंक्शनरीस अच्छा काम करते हैं। हम डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स के लिए इंसेंटीवाईस करने की सोच रहे हैं। Strengthening of Food and Nutrition Boards is of vital importance. मान लीजिए कि अगर आप आज के दिन चाहते हैं कि कुपोषण को हटाएं तो पोष्टिक आहार का रंग, रूप एवं तरीका आप लोग नहीं जानते। यह इन्फोरमेशन और जानकारी कहीं भी नहीं मिलती है, It is important for us to strengthen Food and Nutritious Boards. डिस्ट्रिक्ट एवं स्टेट लेवल तक हमारे पास इन्फोरमेशन रहे, so that we can access this information. हर स्टेट के लिए हमें सोच-समझ कर इलाज करना चाहिए, क्योंकि देश भर में हर स्टेट की समस्या एक नहीं होती है। [s62]

सभापति महोदया, For example, if you take North East, you see, there is a lot of presence of thyroid and goitre. और वहां के लोग अनजाने में वही सब्जी खाते हैं which contributes to goitrogenous disease. ग्वाइटरजनस फूड खाते हैं। लोकल इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी नहीं है लोकल लोग समझते हैं कि लोकल टेस्ट का खाना खाएंगे, तो वहां हम मार खाएंगे क्योंकि लोगों को जानकारी कम है। कई बार because of changing agricultural patterns, our food habits have also altered. For example, in Andhra Pradesh, we had a very interesting incident where in certain villages, there was fluoride water. The grandfathers never had fluoride, but the children showed the impact of fluoride disease. बहुत सारी इन्वैस्टीगेशन करने पर मुझे पता चला कि जब ग्रांड फादर इमली से खाना बनाते थे यानी इमली को निचोड़ कर उसके पानी से वे अपना खाना, सम्बर रसम आदि बनाते थे और उसकी वजह से जो फ्लोराईड होता था वह शरीर से निकल जाता था, लेकिन जैसे ही एग्रीकल्चरल पैटर्न बदला और किसानों ने वहां हाईब्रीड टमाटर उगाने शुरू किए, तो वहां औरतों ने इमली को छोड़कर खटाई के लिए टमाटरों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। टमाटर के इस्तेमाल की वजह से फ्लोराइड शरीर से बाहर नहीं गया। उनकी लाइकोपिन बढ़ती गई, जो उनके लिए अच्छी थी। मगर शरीर से फ्लोराइड बाहर नहीं निकला और वे बच्चे फ्लोराइड के शिकार बन गए। Nutrition and malnutrition, both under-nutrition and over-nutrition, is a very complex subject and it has to be examined in minute, micro detail and we should be able to bring about a solution that is particular to each State so that we can look at the local prevailing situations, what happens in those areas, and how best to combat that with the available resource that is there. There should be no compromise on fortification of food. It is a myth. जो लोग कहते हैं कि फोर्टीफिकेशन करने से वह शरीर पर लागू नहीं होता, यह गलत बात है। There is international experience that shows and there is enough of

our own native intelligence that shows that micro nutrition in optimum levels, micro nutrition fortification, has always helped people. Just like all of us take vitamins, दूध में मिलाने कर पीने के लिए ड्रिंक्स का नाम लेकर लोग इतने बड़े-बड़े एडवर्टाइजमेंट्स छापते रहते हैं और लोगों से पैसे वसूल करते हैं। जब हम अपने लिए लेते हैं, तो हम क्यों नहीं सोचते कि देश के गरीब लोगों के बच्चों का कुपोषण समाप्त करने के लिए मायक्रो न्यूट्रीशन फोर्टीफिकेशन बहुत जरूरी है।

महोदया, इसके साथ-साथ हम नए गोल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ हैल्थ स्टेंडर्ड्स को अपने आप पर लागू कर रहे हैं। इसकी वजह से हम अपने बच्चों के पौष्टिक आहार और उनकी ग्रोथ और डैवलपमेंट को हम ठीक तरह से अंदाज लगाकर मॉनीटर कर सकते हैं, जो बहुत रीयलिस्टिक है। The lowering of annual percentage of malnutrition to 40 per cent, increase in the percentage of severe malnutrition to a national average of 15.8 per cent, the challenge is now to bring down the total malnutrition percentage across the country.

महोदया, दोनों माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छी और वैल्यूएबल सलाह हमें दी है। इसकी वजह से हम देश भर में एक मास न्यूट्रीशन अवेयरनैस कार्यक्रम लागू कर रहे हैं because it is important to give information on nutrition. पहले अपने देश में कई मांएं अपने बच्चों को आदतन स्तनपान कराती थीं, लेकिन आज के दिन हमें मांओं को सिखाना पड़ता है कि बच्चों को स्तनपान कराना चाहिए। बच्चे के पैदा होने के एक घंटे के अंदर-अंदर उसे स्तनपान कराना चाहिए, ताकि Infant mortality can be reduced. बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए उन्हें स्तनपान कराने की बहुत जरूरत है। Changing work patterns, insufficient leave for women who are giving birth to children ये सब देखते हुए, बच्चों पर असर पड़ता है। They become victims of malnutrition. Home scale preservation of fruits, vegetables and nutrition बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि हम अपने घरों में रैफ्रिजरेटर रख कर भी, अगर कुपोषण का शिकार बन सकते हैं, तो आप सोच लीजिए कि आम जनता को, जहां गांवों में कई बार फ्रैश तरकारी भी नहीं मिलती है, कई ट्राइबल एरियाज में जहां लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते रहते हैं, उनकी क्या हालत होगी। हम इस समस्या को हल कैसे करें। यह सोचते हुए, हमने कई इनीशिएटिव्स लिए हैं। दूसरी मिनिस्ट्रीज के साथ काम करते हुए, Iron and folic acid का supplements हम आई.सी.डी.एस. आंगनवाड़ियों के माध्यम से फ्री चिकित्सा हेतु देते हैं।[r63] Vitamin A supplements for children from six months to five years हम लागू कर रहे हैं। National Iodine Deficiency Disorder Control Programme, जो देश भर में लागू है, इसके लिए आपको याद होगा कि कई बार हमने कहा कि नमक का फोर्टीफिकेशन आयोडीन के साथ होना चाहिए। आयोडाइज्ड साल्ट हमें सब को देना चाहिए, क्योंकि आज कोई ऐसी राज्य सरकार नहीं है, जिनके इलाके में कुपोषण नहीं है। So, we have to wake up to reality and move with the modern times and we must be able to embrace latest technologies. भारत देश चन्द्रमंडल पर पहुंच सकता है, पर देश में कुपोषण नहीं हटा सकता है, यह चलने वाली बात नहीं है। This is only because we have not applied ourselves to the issues and we must have a roadmap for eliminating hunger and removing hidden hunger. यह जो गुप्त भूख हमारे लोगों में है, This is of micro nutrition deficiency. लोग सोचते हैं कि चावल दो, अनाज दो तो यह बहुत हो गया। चावल पकाकर दो और पतली सी दाल बच्चों के मुंह पर फेंक दो, यह बहुत खाना हो गया। यह नहीं है। इसमें माइक्रो न्यूट्रिशन की डैफीसिएंसी होती हैं और इस माइक्रो न्यूट्रिशन डैफीशिएंसीज़ को देने के लिए We have to think of fortification of food, जिसकी वजह से हम बच्चों को दे सकते हैं।

हां, प्रधानमंत्री जी ने इन सब समस्याओं को देखते हुए कई इनीशिएटिव्ज़ लिए हैं। जैसे setting up of the National Council of India's Nutrition Challenges for Policy Direction, Review and Effective Coordination between Ministries, ताकि हम देश में कुपोषण के चैलेंज को उठा सकें। Department of Food and Public Distribution, जो तीन प्रोग्राम लागू कर रहा है, Targeted Public Distribution System, Antodaya Anna Yojana, and Annapoorna Scheme, ये तीनों देश भर में आज के दिन लागू हैं। Department of Agriculture and Cooperation has two programmes – increase food production and horticultural intervention. जहां चेंजिंग एग्रीकल्चरल पैटर्न में We should be able to make accessibility to the local citizen; the foods which will be able to give them better seed quality for higher yield of foodgrains so that there is accessibility, availability and affordability of food for the children because they have different eating patterns.

Ministry of Rural Development has two schemes – National Rural Employment Guarantee Programme and Swajal Dhara, जिसकी वजह से लोगों की आमदनी बढ़े, वे कमा सकें और बच्चों के लिए और परिवार के लिए वे पौष्टिक आहार खरीद सकें। यह सब देखते हुए To achieve malnutrition-free India, हमें अलग-अलग स्ट्रेटेजीज़ लागू करनी पड़ती हैं। multi prong, जो सैण्टर और स्टेट लेविल पर अगर हम कर सकते हैं तो फिर हमारे कुछ तरीके होंगे, Investment in nutrition in the 11th Plan हमने बहुत बजट बढ़ा दिया है। Targeting malnutrition. हमारा S.N.P. रेट बढ़ गया है। Calorific norms and the feeding norms for severely mal-nutritioned. हम रिवाइज़ करके लागू करने वाले हैं in a focussed – targeted manner.

मैं सोचती हूं कि इस हाउस में जितने मेरे ऑनरेबिल कुलीग्स हैं, अगर हम सब अपने-अपने क्षेत्र में, इलाकों में इस मुद्दे को उठा सकते हैं, इस पर हम फोकस लगा सकते हैं तो उसका बहुत बड़ा असर होगा, क्योंकि जब आप लोग कुछ कहते हैं तो लोग सुनते हैं। जनता पर उसका असर पड़ता है और लोग समझते हैं कि इसमें कुछ होगा, इसीलिए तो ये सुना रहे हैं। Advocacy and Sensitisation of Parliamentarians. और बाल विवाह जैसी प्रैक्टिसेज़ हैं। इसका हम इसीलिए खंडन नहीं करते हैं कि बच्ची सिर्फ छोटी उम्र की है, लेकिन वह सबसे बड़ी बात है। मगर यह भी बात है कि छोटी लड़की छोटी उम्र में शादी करेगी तो उसी उम्र में वह मां भी बन जाती है और वह खुद जब बालिका है तो वह मां कैसे बन सकती है और मजबूरी में बनेगी भी तो I think you should be able to see. तो मैं सोचती हूं कि हम सब की जिम्मेदारी बनती है। इसमें सरकार की कोई सीमा नहीं है। यह इंसानियत के नाते हमें करना चाहिए कि हम अपने इलाकों में कुपोषण हमेशा के लिए हटा दें। Infant mortality and maternal mortality is very high because she is not ready to become a mother. Physiologically, she is not ready. जो हम बहुत बड़ा मल्टी मीडिया कैम्पेन लेना चाहिए और सब को हर मौके पर बोलना चाहिए, क्योंकि लोग नहीं सोचते हैं कि यह बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसके साथ-साथ जो मेन प्लेयर्स इसमें हैं, We create a climate of nutrition awareness. इसके लिए हम किशोरी शक्ति योजना नाम से एक कार्यक्रम भी चलाते थे।[R64]

18.00 hrs.

ताकि जवान लड़कियों को हम समझायें। School feeding programme, immunization, health intervention, basic hygiene and sanitation, strengthening of public and family health care centres – we have converged most of these programmes at different levels

along with the Ministry of Health. अब कुछ भयंकर स्टैस्टिक्स मैं आपको सुनाऊंगी, जिसे सुनकर हम सबको चौंक उठना चाहिए। In the world, every fifth child lives in India. यह हमारी बड़ी पापुलेशन की वजह से है। Every third under-nourished child in the world lives in India; 22 per cent of babies are born with low birth weight. यह वास्तविकता है। 40.4 per cent of children under three years are under-weight and 15.8 per cent children are severely mal-nourished. 42.5 per cent under five years are under-weight and 15.8 per cent of these children are severely mal-nourished. जब इन संख्याओं को हम देखते हैं, 57 out of 1000 live births do not complete their first year of life. So, breastfeeding of children is very important to protect both mother and child, and we must be able to bring down our levels of infant and maternal mortality. 79.9 per cent children are anaemic. I can also say this that all of you in this Parliament House will find that more than 50 per cent are anaemic.

अहीर जी ने यह भी बात उठायी कि आंगनवाड़ी सेंटर्स में बाथरूम्स होने चाहिए। यह वास्तविकता है। इस मुद्दे को हाउस में उठाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि हम सोचते ही नहीं कि उनकी सहूलियत के लिए एक शौचालय दें। जब तक इर्दगिर्द में सफाई नहीं होगी, तब तक बच्चे बीमारियों के शिकार बनेंगे। क्योंकि वे छोटी उम्र के हैं और कुपोषण के शिकार है, इसलिए उनकी इम्युनिटी कम होती है। They suffer and in turn, it becomes that they are caught in a Catch-22 situation. वे बार-बार बीमार हो जाते हैं, उनका शरीर कमजोर पड़ जाता है, इसकी वजह से दूसरी बीमारियां उनको हो जाती हैं। इसका असर उन पर पड़ता है और वे उसे एक साल की उम्र तक भी पूरा नहीं कर सकते हैं। When you look at all this, you will appreciate that the Ministry of Woman and Child Development has taken on a targeted focussed programme to eliminate mal-nutrition, to reduce mal-nutrition in our country across the board; we have set up different infrastructures, different reporting and monitoring systems and the services in the *anganwadi* centres are also being dovetailed with the Ministry of Health. Now we have increased our *anganwadis* to cover all habitations. We also need help to look at 'nowhere children'. जो स्कूल भी नहीं जाते, काम पर भी नहीं जाते, घर पर रह जाते हैं कि जानवर को चारा देना है, मां-बाप के नौकरी से वापस आने तक खाना पकाकर रखना है, उन बच्चों को तो कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि उनकी जानकारी नहीं होती है। We should be able to cover the nutrition safety net. Even those children should be brought under this cover. All the funds for construction are not allocated, but the efforts are being made. मैंने एमपीलैड्स कमेटी से भी इजाजत ली कि एमपी के एमपीलैड फंड से हम आंगनवाड़ी बना सकते हैं। We have written to the Ministry of Panchayati Raj, that they should allocate lands from the Panchayati Raj to us and help us to construct *anganwadis.*

आंगनवाड़ी चलाने का काम हमारा है, उसे हमारे हाथों पर छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें राजनीतिक तौर से कोई इलेक्शंस नहीं होते हैं, यहां काम होता है। It is the most apolitical and most secular network of India. हर आंगनवाड़ी में हर कम्युनिटी के लोग आते हैं। यहां माताएं और बच्चे आकर एक दूसरे की देखभाल भी करते हैं। It should be respected and left in that condition.

Minimum wages for *anganwadis* is what Shri Sudhakar Reddy has recommended. It would be very nice, but it is not possible at this moment. We will look into the recommendations of the Standing Committee on Labour immediately, if it will, in some way benefit the *anganwadi* teachers. We are ready for that.

Some States are paying some honorarium, which is extra. But I have requested all the State Governments. आंगनवाड़ी टीचर्स पर आंगनवाड़ी काम के अलावा जो दूसरे काम थोप देते हैं, तो उसके लिए they should pay extra. They should not exploit *anganwadi* teachers because they are doing critical and crucial services. Without the *anganwadi* teachers, nowadays, we cannot move forward; they should be recognized, respected and given their due; and all of us should be able to support them. The States should be pressurised into contributing towards their honorarium. [p65]

MADAM CHAIRMAN : You must give them permanent job there.

श्रीमती रेनुका चौधरी : अगर हाउस की सिफारिश मिल जाएगी तो why should we not be able to do that?

Along with this, the other factor that influences is even a thing like malaria impacts on anaemia. Malaria predisposes the human body towards anaemia and we should be able to take cognizance of all the other Ministries which work with us. About 14 Ministries interact with us and these 14 Ministries are to be sensitised towards the needs of women and children. It is my national mission that we will be able to bring down malnutrition and some day eradicate malnutrition because all of us know that by 2015 India is going to be the host country to the youngest productive population in the world. So, we will be contributing not just people but also intelligence, productivity to the world. Hence, it is important for us to pay attention to our children and feed them today because it costs 33 per cent more to correct malnutrition. It is cheaper to spend on feeding our children. I am proud to say that this Government taking that into consideration increased the supplementary nutrition food component much more than ever before. I hope with the cooperation of this House we will be able to dramatically reduce malnutrition in the country one day.

MADAM CHAIRMAN: Thank you, hon. Minister for giving more details on this.

...(*Interruptions*)

सभापति महोदया : अहीर जी, माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छी तरह बताया है। मैंने तो उन्हें थैंक्स कहा है।

â€¦(व्यवधान)

श्री हंसराज गं. अहीर : मैं जानना चाहता हूं कि जो गांव पीने के पानी में फ्लोराइड के प्रमाण से ग्रसित हैं, मैडम ने उल्लेख किया है इसलिए मैं कह रहा हूं, फ्लोराइड वाला गांव आइडैंटीफाइएबल होता है। क्या आप उन गांवों के लिए कोई विशेष कार्यक्रम चलाना चाहती हैं?

इसके अलावा मैं एक अन्य प्रश्न पूछना चाहता हूं। आपने मलेरिया के बारे में कहा।...(व्यवधान)

सभापति महोदया : आपको मंत्री जी बताएंगे।

â€¦(व्यवधान)

श्री हंसराज गं. अहीर : सभापति महोदया, मैंने इससे पहले भी कहा था कि मैं अकेले मंत्रालय पर पूरी जिम्मेदारी डालना नहीं चाहता। ग्रामीण विकास मंत्री यहां बैठे हैं...(व्यवधान)

सभापति महोदया : अहीर जी, किन-किन गांवों में फ्लोराइड युक्त पानी है, यह देखकर मंत्री जी आपको अलग से बता देंगे।

...(व्यवधान)

श्री हंसराज गं. अहीर : मैंने जो प्रश्न किया है, उसका जवाब तो आना चाहिए।...(व्यवधान)

ग्रामीण विकास मंत्री (डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह): फ्लोराइड युक्त गांवों में अलग से फ्लोराइड मुक्त करके सेफ ड्रिंकिंग वाटर उपलब्ध हो, उसके लिए अलग से योजना है।...(व्यवधान) उसे शुद्ध करके साफ पीने का पानी देने का प्रबंध है।